

108

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1744-एक/2014 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 27-5-14 - पारित द्वारा - नाथव तहसीलदार विदिशा -
प्रकरण क्रमांक 86-अ-6/2007-08

नीटूमल पुत्र स्वर्गीय हरीराम बलेचा
मेघदूत टाकीज के सामने
कागदीपुरा जिला विदिशा म०प्र०
विरुद्ध

---आवेदक

- 1- भगवान दास 2- हुकुमचंद
पुत्रगण स्व. सूरजमल बलेचा
- 3- बबली पुत्री सूरजमल बलेचा
- 4- धनवंती पत्नि स्व.सूरजमल
मृतक वारिस अना. 1 से 3
निवासीगण सिंधी कालोनी गंज बासोदा
- 5- भाउ पुत्र गुलाबराय
- 6- श्रीचंद भाउ पुत्र गुलाबराय
तिलक चौक तहसील व जिला विदिशा

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनांक 17-2-2016 को पारित)

यह निगरानी नाथव तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण
क्रमांक 86-अ-6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक
27-5-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959
की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

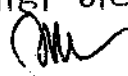


2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि भगवानदास , हुकुमचंद ने तहसीलदार विदिशा को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत कस्बा विदिशा स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 3.135 हैक्टर पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की। सुनवाई के दरम्यान आवेदक ने दिनांक 25-2-14 को आपत्ति प्रस्तुत की। तथा बसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन भी दिया। नायब तहसीलदार विदिशा ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 27-5-14 पारित किया तथा आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त करते हुये निर्णय लिया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद विचारित भूमि मे आपत्तिकर्ता के स्वत्व नहीं मानने से वह नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार नहीं हो सकता, केवल आपत्ति पेश कर सकता है तथा आपत्तिकर्ता द्वारा विलम्ब से पेश बसीयतनामा दिनांक 20.4.07 के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया तथा प्रकरण अन्य पक्षकारों की सुनवाई हेतु आगामी तिथी के लिये नियत किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.6.13 से तहसीलदार की नामान्तरण कार्यवाही पर स्थगन था एवं स्थगन समाप्त होने के उपरांत पुनः कार्यवाही प्रारंभ हुई एवं आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा प्रथक से आवेदन देकर बसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण चाहा गया। इस आवेदन पर इस्तहार जारी






नहीं किया और न ही अनावेदक क्रमांक 1 से 6 ने कोई उत्तर प्रस्तुत किया। पटवारी से भी रिपोर्ट नहीं मँगाई गई। मात्र प्रारंभिक बहस सुनकर आपत्ति एवं नामान्तरण आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने नायव तहसीलदार के आदेश को उचित बताते हुये प्रकरण में आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना बताते हुये आवेदक द्वारा की गई निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं नायव तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 86-अ-6/ 2007-08. में पारित आदेश दिनांक 27-5-2014 के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण निर्णीत होने के बाद एवं वादोक्त भूमि से आवेदक के हित जुड़े न होना पाकर आपत्ति आवेदन निरस्त किया है जिसके कारण उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जब आवेदक का बसीयतनामा माननीय उच्च न्यायालय ने वैध नहीं माना है ऐसे बसीयतनामे के आधार पर आवेदक को नामान्तरण कराने की पात्रता न होना मानकर नायव तहसीलदार विदिशा द्वारा आदेश दिनांक 27-5-2014 से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 86-अ-6/ 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 27-5-2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।


(एम०के०सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

